

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<b>Published by Authority</b>
	आषाढ़ 01, बुधवार, शाके 1944-जून 22, 2022 <i>Asadha 01, Wednesday, Saka 1944- June 22, 2022</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**वित्त(जीएण्डटी) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, जून 22, 2022**

**जी.एस.आर.402 :-**राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 25-01-2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,  
संयुक्त शासन सचिव।

**वित्त (जी एण्ड टी) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, जनवरी 25, 2022**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 32 के सामने,-

- (i) स्तंभ 2 की मद (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति “वृद्धाश्रम इत्यादि में।” के स्थान पर अभिव्यक्ति, “वृद्धाश्रमों, कारागारों, उप-कारागारों, अस्पतालों, उद्धार गृहों, आश्रय-गृहों, उत्तररक्षा गृहों, पुलिस मेस इत्यादि में।” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) स्तंभ 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति “आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, उनसे ऊपर वर्णित मदों के आदेश देने से पूर्व क्रय समिति के माध्यम से दरों के विषय में बातचीत करेगा।” के स्थान पर अभिव्यक्ति, “आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और कारागारों, उप-कारागारों, अस्पतालों, उद्धार गृहों, आश्रय-गृहों, उत्तररक्षा गृहों, पुलिस मेस की उपापन संस्थाएं, उनसे ऊपर वर्णित मदों के आदेश देने से पूर्व क्रय समिति के माध्यम से दरों के विषय में बातचीत करेंगी।” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (iii) स्तंभ 2 में विद्यमान मद (2) और स्तंभ (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

[सं.एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,  
संयुक्त शासन सचिव।

---

Government Central Press, Jaipur.